दृष्टि
The Vision

सामान्य अध्ययन (टेस्ट - XXI)

GENERAL STUDIES (Test - XXI)

मॉड्यूल - XXI / Module - XXI

DTVF/18(JS)–M–GS21

निर्धारित समय: तीन घंटे ***Time allowed: Three Hours***	*अधिकतम अंक: 250* ***Maximum Marks: 250***

नाम (Name): Anoop Meena

क्या आप इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं? | हाँ | ✓ | नहीं | |

मोबाइल नं. (Mobile No.):

ई-मेल पता (E-mail address):

टेस्ट नं. एवं दिनांक (Test No. & Date): 21 / Aug. 20, 2018

रोल नं. [यू.पी.एस.सी. (प्रा.) परीक्षा-2018] [Roll.No. UPSC (Pre) Exam-2018]:

0	8	3	4	4	6	9

परीक्षा का माध्यम (Medium of Exam.): हिंदी

विद्यार्थी के हस्ताक्षर (Student's Signature): [signature]

नोट: प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश अंतिम पृष्ठ पर संलग्न है।

Evaluation Analysis

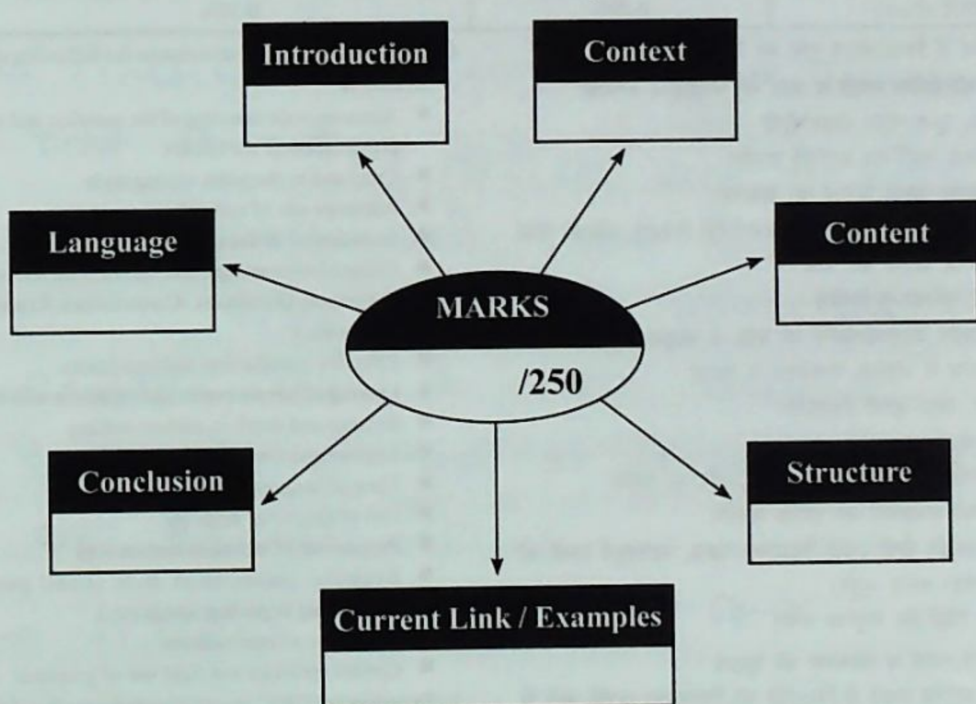

मूल्यांकनकर्त्ता (कोड तथा हस्ताक्षर)
Evaluator (Code & Signatures)

पुनरीक्षणकर्त्ता (कोड तथा हस्ताक्षर)
Reviewer (Code & Signatures)

मूल्यांकन की पद्धति

प्रिय अभ्यर्थियों,

आपकी उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते हुए परीक्षक-समूह के सदस्य निम्नलिखित निर्देशों का ध्यान रखते हैं। आप भी इन्हें ध्यान से पढ़ें ताकि आप अपने प्राप्तांकों का तार्किक कारण समझ सकें।

परीक्षकों के लिये निर्देश

1. मूल्यांकन में अंकों का वही स्तर रखा जाना चाहिये जैसा संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के परीक्षकों द्वारा रखा जाता है।
2. सामान्य अध्ययन का जो उत्तर हर दृष्टिकोण से सटीक व उत्कृष्ट है; उसे अधिकतम 60% अंक दिये जाने चाहियें क्योंकि आयोग द्वारा किये जाने वाले मूल्यांकन में भी इससे अधिक अंक मिलना लगभग असंभव है। वैकल्पिक विषयों के उत्कृष्ट उत्तरों तथा श्रेष्ठतम निबंधों में अधिकतम 70% तक अंक दिये जा सकते हैं।
3. कृपया अंकों का वितरण निम्नलिखित तालिका के अनुसार करें-

Method of Evaluation

Dear Candidates,

While assessing your answer-scripts, the evaluators are required to follow the given instructions. You should also read them carefully to understand the logic behind the marks obtained by you in the tests.

Instructions for the Evaluators

1. The level of marks while evaluating the answers should be kept as per UPSC (Union Public Service Commission) standards as far as possible.
2. The answers of General Studies which are accurate and excellent from every perspective should be awarded a maximum of 60% marks as it is almost impossible to get more than that in actual UPSC examination. Excellent answers in optional subjects and the best written essays can be awarded a maximum of 70% marks.
3. Please assign the marks according to the following table-

उत्तर का स्तर (Standard of Answer)	सामान्य अध्ययन में अंक-स्तर (Marks Standard G.S.)	वैकल्पिक विषय तथा निबंध में अंक-स्तर (Marks Standard - Optional Subject and Essay)
उत्कृष्ट (Excellent)	51-60%	61-70%
बहुत अच्छा (Very Good)	41-50%	51-60%
अच्छा (Good)	31-40%	41-50%
औसत (Average)	21-30%	31-40%
कमज़ोर (Poor)	0-20%	0-30%

4. कृपया उत्तर में निम्नलिखित गुणों को विशेष प्रोत्साहन दें-
   - प्रश्न की सटीक समझ व उत्तर की व्यवस्थित रूपरेखा
   - संक्षिप्त, टू-द-पॉइंट लेखन शैली
   - प्रामाणिक तथ्यों का समुचित उपयोग
   - अधिकतम ज़रूरी बिंदुओं का समावेश
   - सरकारी दस्तावेज़ों (मंत्रालयों/आयोगों की रिपोर्ट्स, पॉलिसी पेपर्स आदि) के संदर्भों की चर्चा
   - प्रभावी भूमिका व निष्कर्ष
   - समकालीन घटनाओं/प्रसंगों को उत्तर से जोड़ना
   - दृष्टिकोण में संतुलन, समावेशन व गहराई
   - अच्छी, साफ-सुथरी हैंडराइटिंग
   - भाषा में प्रवाह
   - आवश्यकतानुसार डायग्राम्स, नक्शों आदि का प्रयोग
   - तकनीकी शब्दावली का सटीक उपयोग
   - सुंदर प्रस्तुति शैली (छोटे पैराग्राफ्स रखना, महत्त्वपूर्ण शब्दों को अंडरलाइन करना आदि)
   - विराम चिह्नों का समुचित प्रयोग
   - भाषा में वर्तनी व व्याकरण की शुद्धता
5. टॉपर्स के अनुभव बताते हैं कि उत्तर की विषयवस्तु अच्छी होने पर आयोग के परीक्षक शब्द-सीमा के थोड़े बहुत उल्लंघन पर अंक नहीं काटते हैं। कृपया आप भी इसी दृष्टिकोण के अनुसार अंक-निर्धारण करें।

4. Please devote special attention to the following qualities in an answer–
   - Accurate understanding of the question and systematic presentation of the answer
   - Crisp and to the point writing style
   - Adequate use of authentic facts
   - Inclusion of all the important points
   - Citing of relevant facts and figures from relevant official documents (Ministries /Commissions Reports, Policy Papers etc.)
   - Effective introduction and conclusion
   - Linking of current events and situations with the answer
   - Balance and depth in answer-writing
   - Legible and clean handwriting
   - Flow of language
   - Use of diagrams, maps etc
   - Precise use of technical terminology
   - Beautiful presentation style (small paragraphs, underlining important words etc.)
   - Proper use of punctuations
   - Correct spellings and right use of grammar
5. Experience of UPSC toppers also indicates that if the content of the answer is good, the UPSC examiners do not cut the marks on slight violations of the word-limit. Please award marks strictly according to the above-mentioned instructions.

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

1. समय-समय पर राज्यसभा के अस्तित्व पर प्रश्न चिह्न उठते रहे हैं। राज्यसभा की भूमिका पर उठने वाले सवालों के कारणों की चर्चा करते हुए इसकी प्रासंगिकता को रेखांकित कीजिये। (200 शब्द) 12.5
The existence of Rajya Sabha often comes under threat. Highlight the significance of Rajya Sabha and discuss the reasons that question its role. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान कुछ न लिखें।
(Please don't w anything in this

राज्यसभा भारतीय संसदीय प्रणाली के उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। यह भारतीय संघीय प्रणाली के अनुरूप राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है।

राज्यसभा की भूमिका एक संशोधनकारी व परामर्शकारी सदन के रूप में कल्पना की गयी थी। परंतु हाल में राज्यसभा की भूमिका पर सवाल उठने के निम्नलिखित कारण है—

→ राज्यसभा ने संशोधनकारी व परामर्शकारी सदन की अपेक्षा अवरोधक सदन की भूमिका को अख्तियार करने लगी है।

दरअसल राज्यसभा अल्पकालिक राजनीतिक हितों के कारण सरकार के प्रत्येक विधायी कार्य का विरोध करने का घर बन चुकी है।

→ राज्यसभा को राज्यों के हितों के रूप में रखा गया था परंतु यह दलीय हितों

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

की सर्वोच्चता प्रदान करने लगी है

→ राज्यसभा में अपराधीकरण होने लगा है। अर्थात् राज्यसभा में धनबल, बाहुबल व हारे हुए प्रतिनिधि आने लगे हैं जिससे विशेषज्ञता का पहलू कहीं छूट गया है

→ यह विधायी कार्यों में संसदीय प्रभाविता को कम करके विलंबन बढ़ाने लगी है जिससे जनकल्याणकारी नीति प्रभावित होने लगी है।

परंतु निम्नलिखित रूप में राज्यसभा की प्रासंगिकता है-

→ यह विशेषज्ञ, तटस्थ, सत्यनिष्ठ व ईमानदार लोगों को प्रवेश देने में महती भूमिका निभा सकती है। जिसका लाभ नीति निर्माण & विधि निर्माण व संसदीय समितियों में किया जा सकता है

→ संघीय प्रणाली के अनुरूप राज्यों का प्रतिनिधित्व करने, नयी लोकसेवाओं का सृजन करने के लिए महत्वपूर्ण है

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

→ लोकसभा द्वारा जल्दीबाजी में बनायी गयी विधियों की समीक्षा हेतु यह संशोधनकारी भूमिका निभाने में समर्थ रही है

→ मनोनीत सदस्यों के माध्यम से यह विविध क्षेत्रों से प्रतिनिधियों को आकर्षित करती है।

राजनीतिक सम्मति के माध्यम से व लोकतांत्रिक सुधारों के माध्यम से राज्यसभा की भूमिका को पुनः प्रभावीरूप से स्थापित किया जा सकता है॥

कृपया इस स्थान कुछ न लिखें।
(Please don't w anything in this

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

2. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित किन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये अभी और प्रयास किये जाने की आवश्यकता है? तर्क सहित चर्चा कीजिये। (200 शब्द) 12.5

Certain goals laid in the Preamble of the Constitution are yet to be achieved and thus need additional efforts. Discuss. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्पण कहा जाता है। केशवानंद भारती वाद व मिनर्वा मिल्स वाद में इसे आधारभूत संरचना का भाग माना गया।

प्रस्तावना में समानता का आदर्श वर्णित है। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 व अनु॰ 39 में इसका प्रावधान है। सामाजिक समानता प्राप्त करने के लिए और प्रयास जरूरी है क्योंकि जनजातियों, महिलाओं, अल्पसंख्यक, दिव्यांगों की स्थिति में अभी पर्याप्त सुधार नहीं हुआ है

2017 में शीर्ष 1% लोगों ने 73% संपत्ति अर्जित की। 1/4 लोग अभी भी गरीब हैं। बेरोजगारी सतत रूप से बढ़ रही है। अत: आर्थिक समानता भी जरूरी है

वर्तमान में न्यायपालिका में 3.3 करोड़ मामले लंबित है अत: न्याय के बेहतर वितरण

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

, सुगम व सस्ती पहुँच हेतु प्रयास जरूरी है। इसलिए न्यायाधीशों की नियुक्ति, वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली का प्रयोग किया जा सकता है।

हम भारत के लोग में शक्ति के विकेंद्रीकरण व जनसंप्रभुता का छिपा है अतः स्थानीय स्वशासन में लैंगिक न्याय के साथ-साथ स्थानीय संस्थाओं को सुदृढ़ करने की जरूरत है वहीं लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभाओं को और अधिक जनोन्मुखी व उत्तरदायी बनाने की जरूरत है।

वर्तमान में मॉब लिंचिंग, सामाजिक बहिष्कार जैसी घटनाएँ बढ़ी हैं अतः बंधुत्व के आदर्श व सांप्रदायिक सौहार्द्र के लिये सुधार जरूरी है। भाषायी, नस्लीय पेचीदगियों से हमको दूर रहना होगा।

पंथनिरपेक्ष की भावना के अनुरूप सरकारों को कार्य करना चाहिए। चुनावों में धार्मिक पृथकतावाद की अवधारणा को नहीं अपनाना चाहिए।

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

अंततः वैचारिक स्वतंत्रता को कम से कम नियमित करना, समाजवाद को वास्तविक अर्थ में स्थापित करने की जरूरत है तब ही हमारी प्रस्तावना के आदर्श फलीभूत होंगे।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

3. विधानसभा के गठन में राज्यपाल की भूमिका की चर्चा कीजिये। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि हाल ही में गठित कुछ विधानसभाओं में राज्यपाल की भूमिका संदिग्ध रही है? तार्किक विश्लेषण कीजिये। (200 शब्द) 12.5

Discuss the role of Governor in the formation of the legislative assembly. Do you agree with the view that in some of the recently constituted legislatures the Governor's role has been questionable? Analyse. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

राज्यपाल राज्य में सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। यह संघीय प्रणाली में केंद्र व राज्य सरकार के मध्य पुल की भूमिका निभाती है।

विधानसभा के गठन में राज्यपाल की मुख्य भूमिका मुख्यमंत्री की नियुक्ति व दल को सरकार के निर्माण हेतु आमंत्रित करने के रूप में होती है जो निम्नलिखित रूप में है—

→ बहुमत प्राप्त करने वाले दल को आमंत्रित करना।
→ चुनाव पूर्व गठबंधन, जिसने बहुमत हासिल किया है, को आमंत्रित करना।
→ चुनाव उपरांत गठबंधन जिसने बहुमत हासिल करने का दावा किया है।

यदि किसी दल या गठबंधन को बहुमत नहीं मिला है तो—

→ सर्वाधिक सीटें प्राप्त करने वाले दल

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

दल या चुनाव पूर्व गठबंधन दल या चुनाव के उपरांत गठबंधन को सरकार के निर्माण हेतु आमंत्रित करना।

मानतीय सर्वोच्च न्यायालय ने एस. आर. बोम्मई वाद में कहा है कि "सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले दल को ही या गठबंधन को ही सरकार बनाने का अधिकार है"

परंतु हालिया कर्नाटक चुनाव में संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हुआ एवं राज्यपाल ने राजनीतिक कारणों से प्रेरित होकर सबसे अधिक सीटें प्राप्त करने वाले एकल दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जबकि सर्वाधिक सीटें किसी अन्य गठबंधन ने प्राप्त की थी।

जबकि गोवा, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड में सर्वाधिक सीट प्राप्त करने वाले गठबंधन की सरकार बनी थी

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः S.R. बोम्मई वाद के निर्णय को दोहराया कि राज्यपाल को राजनीतिक एजेंट की भूमिका न निभाते हुए राज्य की जनता व संवैधानिक प्रतिनिधि की भूमिका निभानी चाहिए।

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

4. मूल कर्त्तव्यों में वर्णित मूल्य यद्यपि आम लोगों की समझ से परे हैं, साथ ही यह बाध्यकारी भी नहीं हैं, तथापि इसके महत्त्व को नकारा नहीं जा सकता है। स्पष्टीकरण कीजिये। (200 शब्द) 12.5

The values enshrined in the Fundamental Duties are beyond the understanding of common people and are not binding, yet their importance cannot be denied. Elucidate. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में है इन्हें 42वे संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर जोड़ा गया था।

भारतीय ~~प्रतीक~~ प्रतीकों जैसे ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना; वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना आदि प्रमुख मूल कर्त्तव्य है।

मूल कर्तव्य, मूलाधिकारों के समान न्याय/वादयोग्य नहीं है अतः यह नागरिकों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है परंतु प्रायः प्रत्येक नागरिक से इनके पालन की अपेक्षा की जाती है सरकार, न्यायपालिका या विधायिका इनको नागरिकों पर आरोपित नहीं कर सकती है।

परंतु इनका पर्याप्त महत्व है। ये नागरिकों में एकता की भावना विकसित

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

करते हैं। जैसे राष्ट्रगान व राष्ट्रध्वज का सम्मान करना।

प्राथमिक शिक्षा जैसे मूलकर्त्तव्य का महत्व इतना था कि इसको मूलाधिकार का दर्जा दिया गया।

मूलकर्त्तव्य प्रगतिशील समाज की पहचान है। ये लैंगिक न्याय, महिला विरोधी प्रथा, बाल श्रम आदि के शमन हेतु लोगों को प्रेरित करते हैं।

ये नागरिकों में वैज्ञानिक चेतना, तार्किकता विकसित करने का प्रयास करते हैं। ये बताते हैं कि मानव के अधिकारों के साथ-साथ कुछ कर्त्तव्य भी होते हैं अतः इनका पालन करना चाहिए ताकि समाज में अराजकता की स्थिति पैदा न हो।

ये भारतीय एकता, विविधता में एकता, संप्रभुता, वैचारिक समन्वय, समरसता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

कई मूलकर्त्तव्यों का तो इतना महत्व है कि उनको विधिक रूप दिया गया है- जैसे - राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान निवारण एक्ट 1971, शिक्षा का अधिकार एक्ट 2009 आदि। अब इनका पालन प्रत्येक नागरिकों हेतु अनिवार्य है

समग्र रूप में कहा जाये तो ~~मूलाधिकार~~ मूलकर्त्तव्य सरकार की नागरिकों से वैधानिक अपेक्षायें है जिनके पालन की वे प्रत्येक नागरिक से उम्मीद करती है

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

5. 'जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33(7)' को स्पष्ट कीजिये। क्या यह अधिनियम भ्रष्टाचार, प्रशासनिक शिथिलता व अनावश्यक वित्तीय बोझ को बढ़ावा देता है। इस अधिनियम के संदर्भ में चुनाव आयोग द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों की चर्चा कीजिये? (200 शब्द) 12.5

Explain the 'Section 33(7) of the Representation of People Act'. Does it promote corruption, administrative laxity and unnecessary financial burden? Discuss the various steps taken by the Election Commission with respect to it. (200 words) 12.5

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33(7) एक उम्मीदवार अधिकतम 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है, के संदर्भ में है

मूलधारा में यह प्रावधान था कि उम्मीदवार कितनी भी सीटों से चुनाव लड़ सकता है। परंतु दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशों के आधार पर इसे सीमित करके सीमा को 2 सीटों तक नियत किया।

यह प्रणाली चुनावों में धनबल को बढ़ावा देती है इसके माध्यम से अमीर लोग एकसाथ कई चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ते है जिससे वे धन के बल से जीतने की पर्याप्त कोशिश करते है वे मतदाताओं को खरीदने से भी नहीं चूकते है

कृपया इस स्थान में ... कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

एक साथ एकाधिक सीटों से चुनाव लड़ने पर सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग होता है एवं पुनः चुनाव कराने पर अतिरिक्त खर्च होता है।

इससे विद्यालय, प्रशासनिक मशीनरी, कल्याणकारी गतिविधियाँ आदर्श आचार संहिता के कारण बाधित होती है।

चुनाव आयोग ने यह कहा है कि जब देश में एक मतदाता - एक मत का सिद्धांत है तो एक उम्मीदवार - एक सीट का सिद्धांत भी होना चाहिए। यह जनविश्वास को बनाए रखेगा।

चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि उपचुनावों के खर्च का भार सीट छोड़ने वाले उम्मीदवार पर डालना चाहिए।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

6. रोस्टर सिस्टम क्या है? इससे जुड़े प्रमुख विवादों की चर्चा कीजिये। हाल ही में लाए गए रोस्टर अधिसूचना की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिये। (200 शब्द) 12.5
What is the Roster System? Discuss the major issues associated with it and enumerate the key features of the recently issued Roster notification. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

रोस्टर सिस्टम का उदय
श्री जजेस केसेज में हुआ।

यह भारतीय न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग है इसमें यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यह निर्धारित करेगा कि कौनसा केस किस न्यायाधीश द्वारा सुना जाएगा।

सामान्यत: उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (CJI) द्वारा वरिष्ठता व विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए केसों का आवंटन किया जाता है।

परंतु हाल में कई न्यायाधीशों ने यह आरोप लगाया कि CJI केसों का आवंटन वरिष्ठता को ध्यान में न रखते हुए जूनियर न्यायाधीशों को हस्तांतरित कर रहे हैं। साथ ही वे

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान कुछ न लिखें।
(Please don't w anything in thi

इस मामले में विशेषज्ञता व वरिष्ठता का ध्यान भी नहीं रख रहे है।

विवाद यह भी उठा कि CJI Master of the Roster की भूमिका निभा रहा है यह व्यवस्था असंवैधानिक है एवं मूल संविधान में इसका वर्णन नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय ने रोस्टर प्रणाली के संदर्भ में नयी अधिसूचना जारी की है –

→ तृतीय न्यायाधीश केस (1998) में स्थापित रोस्टर प्रणाली संवैधानिक भावनाओं के अनुरूप है।

→ मुख्य न्यायाधीश को विषयों के हस्तांतरण में विशेषज्ञता व वरिष्ठता जैसे मानक ध्यान में रखने चाहिए। परंतु यदि विवाद होता है तो मुख्य न्यायाधीश

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

स्वविवेक से निर्णय लेगा। अतः इस अधिसूचना में भी मुख्य न्यायाधीश को रोस्टर प्रणाली में मुख्य कर्ता-धर्ता मान लिया गया है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

7. वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) मशीन क्या है? ई.वी.एम पर उठ रहे विवाद के संदर्भ में वीवीपैट का प्रयोग निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने में कितना उपयोगी हो सकता है? समीक्षा कीजिये। (200 शब्द) 12.5

What is the Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT)? In the context of the disputes over EVMs, to what extent the use of VVPAT can be useful in ensuring transparency of the election process? Examine. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

वीवीपैट मशीन एक पुनरीक्षण प्रणाली से युक्त मशीन है इसमें जब मतदाता अपना मत डालता है तो मत की स्वीकार्यता के साथ एक कागज की पर्ची भी निकलती है जो यह बताती है कि मतदाता का मत वैध व स्वीकृत हो चुका है

भारतीय चुनाव प्रणाली में तीव्रता व पारदर्शिता बढ़ाने में EVM मशीन का अमूल्य योगदान रहा है

यह मशीन इंटरनेट तंत्र से पूर्णतः पृथक है परंतु हाल में कुछ दलों ने राजनीतिक कारणों से प्रेरित होकर सरकार व चुनाव आयोग पर यह आरोप लगाया कि इसमें हस्तक्षेप कर वोटिंग में गलत संशोधनकारी तरीके अपनाये हैं

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

ऐसी समस्याओं से निपटने में वीवीपैट की महती भूमिका सिद्ध होती है क्योंकि यह मशीन ई०वी० एम० से सम्बद्ध होती है।

इस मशीन में यह रिकॉर्ड रहता है कि किस मतदाता ने किस-किस उम्मीदवारों को मत दिये है। अतः वोटिंग की पुनः गणना व ऐसे आरोपों को निराधार साबित करने के लिए रसीदों की गणना की जा सकती है।

साथ ही यह मशीन इंटरनेट तंत्र से मुक्त है तो इसमें साइबर हमले की या बाहरी हस्तक्षेप की संभावना भी नहीं रहती है।

परंतु चुनाव आयोग ने चुनावों मे इसका प्रयोग करने की सलाह दी है एवं कहा है कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर इस मशीन का सभी उम्मीदवारों पर इसकी तकनीकी सत्यता को जाँचा जा सकता है

Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

इस मशीन के प्रयोग से भारतीय चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता का एक और पक्ष जुड़ जाएगा। यह मशीन वित्तीय रूप से भी व्यावहार्य है अतः इसका प्रयोग किया जा सकता है।

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

8. 'दबाव समूह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिये उपयोगी होते हुए भी कभी-कभी चुनौती प्रस्तुत करते हैं।' कथन के आलोक में दबाव समूह के अर्थ को स्पष्ट करते हुए इनकी भूमिका को उद्घाटित कीजिये। (200 शब्द) 12.5

'The pressure groups, though useful for the democratic system, often present challenges.' In light of the statement, explain the meaning of pressure groups and illustrate their role. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

दबाव समूह से तात्पर्य उस गैर-सरकारी समूह से है जो साझे हित, सिद्धांतों व उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक साझेदारी भूमिका निभाते है।

भारत में स्वतंत्रता के समय से वर्तमान तक दबाव समूहों का पर्याप्त विकास हुआ है। ये धार्मिक, जातिगत, लैंगिक, NGOs का स्वरूप लिये होते है।

ये भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था हेतु निम्नलिखित रूप में उपयोगी है:-

→ सरकार की उपयुक्त आलोचना करते हुए समावेशी व जनकल्याणकारी विधायन बनाने में उनकी महती भूमिका होती है।

→ वंचित व अल्पसंख्यक वर्ग अपनी मांगों को मनवाने के लिए दबाव समूहों का प्रयोग करते हैं। जैसे-

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

ओडिशा में नियामगिरि पहाड़ियों में लोह-संयंत्र की स्थापना का विरोध करना।

→ पर्यावरण के संरक्षण, व सुभेद्य वर्ग या आपदा प्रभावितों लोगों के हितों के लिये भी ये उपयोगी है जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन के समय विस्थापित लोगों को उचित सहायता दिलाना।

→ दबाव समूहों के माध्यम से सरकार की स्वेच्छाचारिता को रोकने में मदद मिलती है।

परंतु निम्नलिखित रूप से ये चुनौती उत्पन्न करते हैं-

→ कई बार दबाव समूह हिंसक गतिविधियों का सहारा लेते हैं जो विधि के शासन का उल्लंघन है जैसे - धार्मिक संगठन, बाबरी मस्जिद मोर आदि।

→ कई बार ये अनुचित मांगें मनवाने के चक्कर में अन्य समुदायों से तनाव मोल ले लेते हैं। जैसा कि हालिया

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

आरक्षण आंदोलनों के समय वैमनस्यकारी तनावों के संदर्भ में देखा गया है

→ ये संविधानवाद का उल्लंघन करते हैं- जैसे मीडिया ट्रायल करना आदि।

→ ये कई बार बाहरी शक्तियों प्रेरित प्रतीत होते हैं। जैसे उत्तर-पूर्वी भारत में अलगाववादी गतिविधियाँ। जिनमें भारतीय संप्रभुता व आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ती है

→ ये पर्यावरण के नाम पर विकास गतिविधियों को बाधित करते हैं जिनसे सामाजिक न्याय, समावेशी विकास की प्रक्रिया बाधित होती है

समग्र रूप से राज्य तंत्र को वैध आलोचना को स्वीकारते हुए अवैध व विघटनकारी गतिविधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

9. मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए इसकी सीमाओं की चर्चा कीजिये। भारत में महिला श्रम बल को अधिक सशक्त बनाने हेतु अधिनियम में सुधार के उपाय भी बताइए। (200 शब्द) 12.5

Highlight the provisions of the Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017 and discuss its limitations. In order to empower the women workforce suggest measures for improvement in the Act. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 बच्चे के पोषणिक स्तर को सुधारने, मातृत्व स्वास्थ्य को ध्यान में रखने के साथ बाल व मातृ मृत्यु दर को नियंत्रित करने के लिये लाया गया था।

इस अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित हैं—

→ यह संगठित क्षेत्र के सभी उद्यमों पर लागू होता है इससे 18 मिलियन महिलायें के लाभान्वित होने की संभावना है (सर्वेक्षण)

→ इसमें मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है

→ 50 से अधिक कर्मचारी वाले उद्यम में क्रेच की सुविधा अनिवार्य है।

→ 2 या 2 से अधिक बच्चे वाली माँ, सरोगेट माँ व दत्तक माँ के लिए 12 सप्ताह का अवकाश होगा।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

→ महिलायें दूरस्थ कार्यप्रणाली के लिए नियोक्ता से अनुमति प्राप्त कर सकती है।

इस अधिनियम की निम्नलिखित सीमायें है

→ यह लैंगिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित है इसमें पितृत्व अवकाश की चर्चा नही है।

→ यह असंगठित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता।

→ इसने केवल माता - पिताओं को कवरेज प्रदान नहीं की है।

→ यह पुरुषों को वरीयता प्रदान करेगा एवं महिलाओं के कैरियर ब्रेक आने की संभावना है।

→ यह महिलाओं के घरेलू कार्य व बच्चो की देखभाल में द्वंद्व उत्पन्न कर सकता है।

अतः इस अधिनियम में सुधार के लिए जरूरी है कि पितृत्व अवकाश को भी शामिल करके इसे लैंगिक न्याय, समानता, भावनात्मक स्वरूप प्रदान किया जाए।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

सिंगापुर मॉडल को अपनाया जाए जिसमें अवकाश की क्षतिपूर्ति सरकार व नियोक्ता दोनों वहन करें।

जब महिला पुनः कार्य पर लौटती है तो उसे कार्यदशाओं में लचीलापन प्रदान किया जाए।

एकल माता-पिता व छोटे उद्यमों की वित्तीय स्थिति व आवश्यकता को भी संबोधित करना चाहिए।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

11. हाल ही में श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा घरेलू श्रमिकों के हितों की रक्षा हेतु न्यूनतम मज़दूरी एवं सामाजिक सुरक्षा गारंटी देने संबंधी मुद्दों में सुधार किया गया है। सुधार के इस विषय पर नीति की आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए वर्तमान नीतिगत मसौदे में शामिल किये गए प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालिये। (200 शब्द) 12.5

Recently, in order to protect the interests of domestic workers, the Ministry of Labour and Employment has reformed the rules governing minimum wages and social security guarantees. Discuss the need for policy on this issue and elucidate the key features of the current draft policy. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

यह समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत के अनुरूप है यह असंगठित क्षेत्रों मे प्रचलित मनमानी वेतन प्रणाली के नियमित करने हेतु जरूरी है।

भारत मे कृषि श्रमिक, घरेलू श्रमिकों को नियमित व जीवन जीने योग्य पारिश्रमिक दिलाने हेतु यह जरूरी है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

12. सामाजिक सशक्तीकरण के साथ-साथ आर्थिक सशक्तीकरण में 'सुकन्या समृद्धि योजना' किस प्रकार सहायक है? स्पष्टीकरण कीजिये। (200 शब्द) 12.5

How is the 'Sukanya Samriddhi Scheme' helpful in social as well as economic empowerment? Elucidate. (200 words) 12.5

सुकन्या समृद्धि योजना एक लैंगिक न्याय व लैंगिक समानता की स्थापना करने के लिए चलायी गयी प्रमुख योजना है

यह योजना 10 वर्ष तक की लड़की के लिए बीमा कवरेज व बचत खाते का प्रावधान करती है यह खाता किसी अनुसूचित बैंक में होना चाहिए।

यह योजना बाल विवाह को रोकने की सहायता करेगी। क्योंकि इसमें यह प्रावधान है कि खाते में से राशि 18 वर्ष की आयु के उपरांत ही निकाली जा सकती है, उससे पहले नहीं। उससे पहले निकालने की स्थिति में 9% की दर से ब्याज नहीं मिलेगा।

18 वर्ष के उपरांत शिक्षा,

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान कुछ न लिखें।
(Please don't wr anything in this

स्वास्थ्य के लिए राशि निकली जा सकती है परंतु यह अधिकतम 50% हो सकती है एवं शेष 50% राशि 21 वर्ष के उपरांत निकाली जा सकती है

चूँकि इस योजना में ब्याज की उच्च दर है अत: लडकियां आर्थिक स्वनिर्भरता बढ़ेगी एवं वे रोजगार, उच्च शिक्षा बेहतर स्वास्थ्य रक्षाएं प्राप्त करने में समर्थ हो सकेंगी।

यह योजना लोगों में जागरूकता उत्पन्न करेगी एवं कन्या हत्या जैसे अपराधों को रोककर सामाजिक अभिरुचि में परिवर्तन करने में सहायक होगी। इसमें लिंगानुपात व वर्तमान बाल लिंगानुपात बढ़ने की पर्याप्त संभावना निहित है

चूँकि लडकियाँ पर्याप्त रूप से स्थिर्ता प्राप्त कर सकेंगी इसलिए उनकी परिवार पर आर्थिक निर्भरता कम होने से उनकी निर्णयन क्षमता बढ़ेगी

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

समग्र रूप में इस योजना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना के साथ सम्बद्ध करके बेहतर परिणाम हासिल किये जा सकते हैं।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

13. भारत में बढ़ती बेरोज़गारी की समस्या के निराकरण हेतु 'प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना' कहाँ तक सहायक हो सकती है? इस योजना की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करते हुए, इसके समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। (200 शब्द) 12.5

To what extent the 'Prime Minister's Employment Generation Programme' can be helpful in resolving the problem of rising unemployment in India. Highlight the key features of this programme and discuss its major challenges. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

भारत में प्रतिवर्ष 10 मिलियन लोग श्रम बाजार में शामिल हो रहे हैं परंतु उस अनुपात में विनिर्माण, कृषि व सेवा क्षेत्र में रोजगार सृजन न हो पाने से बेरोजगार बढ़ रही है (मैकिंजे रिपोर्ट)

बेरोजगारी की समस्या का सामना करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गयी है यह योजना सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है

इसमें प्रमुख प्रावधान यह है कि श्रमिकों को प्रशिक्षण, कौशल व नियोजित करने वाले MSMEs आदि उद्यमों को कर्मचारी भविष्य निधि में 8.15 % भाग का अंशदान सरकार देगी साथ इसमें विभिन्न विनियामकीय छूटें जैसे - नियुक्ति फॉर्म कम करना जैसे

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

प्रावधान भी किये गये है

यह योजना बेरोजगारी की समस्या का सामने इस रूप में करेगी क्योंकि इससे उद्यमों को श्रमिक नियुक्त करने में सहायता मिलेगी। क्योंकि सामाजिक सुरक्षा में दिया जाने वाला अंशदान का एक हिस्सा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

साथ ही श्रम में उद्योगों की मांगों के अनुरूप कुशल व प्रशिक्षित श्रमिक भी उपलब्ध होगी।

इस योजना का दूसरा पक्ष यह है कि इसमें श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा अपरिहार्य रूप से मिलेगी क्योंकि सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता सामाजिक सुरक्षा के रूप में है इससे श्रमिक के रोजगार में निश्चितता बनी रहेगी एवं उसे बाजार के अनुरूप कौशल भी मिलेगा।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this

परंतु समस्या है कि यह प्रोत्साहन बेरोजगारी को खत्म करने का मात्र एक अस्थायी उपाय है इसमें सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कौशल प्रशिक्षण जैसी व्यवस्था नहीं की गयी है

साथ ही प्रदत्त सहायता के आउटपुट क्या रहे इसका भी सामाजिक लेखा परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है

इसमें असंगठित क्षेत्र को शामिल नहीं किया है जिन्हें किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा नहीं है अतः इस योजना का लाभकारी प्रभाव बहुत थोड़ा है

सामाजिक लेखा परीक्षा, असंगठित क्षेत्र को शामिल करके व कौशल प्रदान करके रोजगार क्षमता बढ़ाकर इस योजना को प्रभावी बनाया जा सकता है

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

14. भारतीय समाज में असुरक्षित एवं उपेक्षित समुदाय के रूप में पहचाने गए विस्थापित लोगों के विस्थापन के पीछे विद्यमान प्रमुख कारणों की पहचान करते हुए इन समुदायों के द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख समस्याओं को बताएँ तथा इनके कल्याण के लिये आवश्यक समाधान भी प्रस्तुत कीजिये। (200 शब्द) 12.5
The migrants are recognized as vulnerable and marginalised community in Indian society. Discuss the reasons behind their displacement. Also highlight the challenges faced by them and suggest some measures for their welfare. (200 words) 12.5

भारत में विस्थापन एक प्रमुख समस्या रही है यह विभिन्न सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक आयामों से प्रेरित है

विस्थापित लोगों में अधिकांशतः जनजातीय, समुदाय, अल्पसंख्यक व गरीब शामिल है इनके विस्थापन के निम्नलिखित कारण है→

→ विद्युत उत्पादन के लिए जलाशय व बाँधों का निर्माण जैसे सरदार सरोवर बाँध आदि।

→ विकास परियोजनाएँ जैसे हाइवे व सड़कों का निर्माण।

→ उद्योगों की स्थापना। जैसा कि ओडिशा में पास्को स्टील प्लांट के कारण विस्थापित जनजातीय समुदायों के रूप में देखा गया।

→ आपदाओं से प्रभावित लोग। जैसे हालिया समय में उत्तराखंड से पंजाब,

Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

दिल्ली व उत्तरप्रदेश की ओर विस्थापन करते है

→ अन्य कारणों में सामाजिक संघर्ष, नक्सलवाद, नस्लवाद, मॉब लिंचिंग अंतर्राष्ट्रीय कारक (रोहिंग्या) प्रमुख है।

इन समुदायों के निम्नलिखित समस्यायें हैं—

→ आर्थिक स्थिति सुनिश्चित नहीं हो पाती है। क्योंकि ये अपने परंपरागत रोजगार से भिन्न आर्थिक दशायें पाते है

→ इनके पास पहचान की समस्या होने के कारण सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नही उठा पाते है

→ जिस क्षेत्र में ये विस्थापित होते हैं वहाँ सांस्कृतिक समन्वय स्थापित नहीं कर पाते हैं। अतः भाषायी व नस्लवादी संघर्ष सामने आते है.

→ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की पर्याप्त सुविधा न होने से शहरों में मलिन बस्तियों का विकास होता है जिससे इनमें अपराधीकरण व वैश्यावृत्ति की

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

समस्या पायी जाती है

इनकी समस्याओं के समाधान के लिए सर्वप्रथम जरूरी है बेहतर पुनर्वास व्यवस्था करनी चाहिए इनको शिक्षा, आवास, भोजन से संबंधित योजनाओं के लाभ हेतु अस्थायी पहचान प्रणाली प्रदान करनी चाहिए।

यदि परियोजना के निर्माण से इनकी संस्कृति, भूमि छिनती है तो इनको संभव समरूप क्षेत्र में पुनर्वास कराना चाहिए।

इन सुभेद्य समुदायों का अनावश्यक राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। अन्य स्थानीय समूहों में सहयोग, संवेदनशीलता के भाव जागृत करने चाहिए। बड़ी योजना निर्माण से पहले पर्याप्त पर्यावरणीय व सामाजिक प्रभाव आकलन करना चाहिए

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

15. 'मानसिक स्वास्थ्य की बढ़ती समस्या ने सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को बाधित किया है।' कथन का विशदीकरण करते हुए भारत में मानसिक स्वास्थ्य के सम्मुख उपस्थित चुनौतियों को स्पष्ट कीजिये तथा इस दिशा में सरकार के द्वारा किये गए प्रमुख प्रयासों की चर्चा भी कीजिये। (200 शब्द) 12.5

'The problem of mental health disrupts the process of social justice.' Discuss the challenges of mental health in India and highlight the steps taken by the government in this direction. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र की हालत दयनीय है। भारत में सकल सार्वजनिक व्यय, मानव संसाधन आदि की कमी रही है।

मानसिक स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट आ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में मानसिक रोगियों की संख्या 2025 में 8 million होने की संभावना है।

मानसिक स्वास्थ्य मानव की निर्णयन क्षमता को बाधित करता है, अवसाद को बढ़ाता है, पीड़ित व्यक्ति सामाजिक कलंक के रूप में देखा जाता है अतः इनसे उनकी समग्र देखभाल बाधित होने से सामाजिक न्याय बाधित होता है।

मानसिक स्वास्थ्य के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियाँ हैं:-

→ समग्र स्वास्थ्य व्यय का मात्र दसवाँ भाग ही मानसिक स्वास्थ्य पर खर्च किया जाता है अतः वित्तीयन की समस्या है

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाषः 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेलः helpline@groupdrishti.com, वेबसाइटः www.drishtiIAS.com
फेसबुकः facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटरः twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

→ इसे केवल चिकित्सीय समस्या के रूप में देखा जाता है। अतः इसे सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। तब जाकर सामाजिक कलंक न मानकर इनकी सामाजिक स्वीकार्यता को बढ़ाना चाहिए।

→ पर्याप्त अवसंरचना जैसे पृथक आवास, सलाहकार, प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी रहती है।

→ चिकित्सकों व सहायक वर्गों, पुलिस आदि का असंवेदनशील व्यवहार।

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल हेतु निम्नलिखित प्रयास किये है-

→ मानसिक स्वास्थ्य देखभाल विधेयक 2017 के माध्यम से पहचान, चिकित्सा व पुनर्वास प्रणाली अपनाना।

→ सभी जिलों में हाफवे होम्स की स्थापना करके उनको समन्वयकारी व सहयोगी की भूमिका में लाना।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

→ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सलाहकारों की स्थापना करना।

→ अस्पतालों में अनुकूल वातावरण का निर्माण करने का प्रयास किया है एवं अनावश्यक इलेक्ट्रोप्लसिव थेरेपी को रोकने की भी व्यवस्था की गयी है

→ राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में शामिल करना

अत: मानसिक पीड़ित को सामान्य पीड़ित की अपेक्षा अधिक सामाजिक-सरकारी - चिकित्सीय सहयोग की जरूरत होती है

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

16. विकास की रणनीति का अंतिम लक्ष्य सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना है, किंतु भारत के जनजातीय क्षेत्रों में इस रणनीति का विरोध किया गया है। इस विरोध के पीछे विद्यमान कारणों की पहचान करते हुए इसके समाधान हेतु उठाये गए कदमों की चर्चा कीजिये। (200 शब्द) 12.5

The ultimate goal of development is to ensure social justice but in tribal areas of India this strategy has been obstructed. Identify the reasons behind this and discuss the steps to be taken for its resolution. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

भारत में विकास के लिए समय समय पर अनेक योजनायें व कार्यक्रम चलाये गये हैं एवं कुछ हद तक सामाजिक न्याय भी प्राप्त हुआ है जैसे महिला साक्षरता व श्रमबल में भागीदारी बढ़ना आदि।

परंतु यह स्थिति जनजातीय संदर्भ में लागू नही होती। भारत में लगभग 8.5% जनजातीय समुदाय है परंतु ये अभी पर्याप्त विकास नही कर पाये हैं। इनमें निम्न साक्षरता, पारंपरिक आर्थिक क्रियाओं पर निर्भरता, एनीमिया व कुपोषण जैसी समस्यायें विद्यमान हैं।

विकास की इन वर्तमान नीतियों का जनजातियों द्वारा विरोध करने के कारण निम्नलिखित हैं:—

→ उद्योगों की स्थापना से वन अवनयन होता है एवं जनजातियाँ विस्थापित होकर अन्य क्षेत्रों में प्रवास करती हैं।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

जिससे भाषा, सामाजिक समन्वय की समस्या आती है।

→ जनजातियाँ इन विकासात्मक कार्यों को अपने जीवन व संस्कृति में हस्तक्षेप के रूप में देखती है अतः इनकी रक्षा की प्रतिक्रियास्वरूप वे विरोध करती है।

→ इन गतिविधियों के कारण उनका शोषण बढ़ता है जैसे पर्याप्त शिक्षा न होने के कारण मनचाहा वेतन मिलता है।

→ जनजातियों के वन्योत्पादों पर उनका नियंत्रण नहीं है। उनका व्यावसायीकरण करने से वे विरोध करते हैं।

→ निर्णयन संस्थाएँ जैसे पंचायती राज में उनकी कम भागीदारी है।

सरकार ने इस दिशा में निम्नलिखित कदम उठाये हैं-

→ सामाजिक शोषण से मुक्ति के लिए अत्याचार निवारण अधिनियम 1989

→ स्थानीय संस्थाओं में पर्याप्त भागीदारी

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

व ग्रामसभाओं के सशक्तिकरण के लिए पंचायती राज संस्थाओं का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार (PESA) Act 1996।

→ वन्योत्पादों पर नियंत्रण, संग्रहण, विक्रय हेतु वनाधिकार एक्ट 2006।

→ जनजातीय उद्यमिता नीति, स्टैंडअप स्कीम, एकलव्य मॉडल आवासीय योजना, राष्ट्रीय SC केंद्र आदि का क्रियान्वयन।

अतः इन समाधानकारी उपायों में जनजातीय भागीदारी बढ़ाकर, उनमें जागरूकता का प्रसार करके उनको मुख्य धारा में लाया जा सकता है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

17. भारतीय प्रधानमंत्री की हालिया चीन यात्रा के महत्त्व को रेखांकित करते हुए वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत-चीन संबंधों में हो रहे उतार-चढ़ाव की समीक्षा कीजिये। (200 शब्द) 12.5

Highlight the significance of Indian Prime Minister's recent visit to China and analyse the shifts in India-China relations in the current global scenario. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

भारत व
चीन के मध्य
हालिया अनौपचारिक
यात्रा संपन्न हुयी
एवं वुहान
घोषणापत्र
पर हस्ताक्षर
हुए
इसमें भारत के कई
पक्षों जैसे
आतंकवाद का विरोध,

व्यापार घाटा को संतुलित करने में भारत की सहायता करने, सीमा विवाद हल करने में चीन ने भारत का समर्थन किया है वही भारत ने संरक्षणवाद पर व नियम आधारित व्यवस्था पर भारत का समर्थन किया है

परंतु भारत व चीन के मध्य निम्नलिखित तनाव के बिंदु हैं —

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

→ सीमाविवाद । चीन अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा न मानकर दक्षिण तिब्बत का भाग मानता है।

→ सुरक्षा परिषद व NSG मे भारतीय सदस्यता का चीन द्वारा विरोध करना

→ भारतीय संप्रभुता की अवहेलना करते हुए पाक अधिकृत कश्मीर से चीन-पाक० आर्थिक गलियारा का निर्माण।

→ अघोषित स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति।

→ भारत व चीन के मध्य $ 84 b का व्यापार है जिसमें भारत को $51 b का व्यापार घाटा है

→ दक्षिण चीन सागर व हिंद महासागर मे चीन की आक्रामकता, आतंकवाद पर दोहरा रवैया आदि चिंता के विषय है।

परन्तु भारत व चीन के मध्य कुछ सहयोग के बिंदु भी है-

→ वार्ता के माध्यम से सीमा विवाद हल करना।

→ ब्रिक्स, SCO जैसी वैश्विक संस्थाओं

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

में सदस्यता

→ नियम आधारित व्यापार व्यवस्था के आधार विश्व व्यापार संगठन को बनाये रखना।

→ विश्व में बढ़ते संरक्षणवादी रवैये का विरोध करना।

→ अफ्रीका का विकास, 21वीं सदी एशिया की सदी आदि सहयोग के बिंदु है।

परंतु भारत को चीन के साथ संतुलित विदेश नीति अपनानी चाहिए। इसमें स्मार्ट पावर (हार्ड पावर व सॉफ्ट पावर) का समावेशन होना चाहिए

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

18. भारत के लिये बिम्सटेक 'नेबरहुड फर्स्ट' और 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' दोनों के लिये महत्त्वपूर्ण है। कथन को विस्तार देते हुए क्षेत्रीय साझेदारियों के प्रति भारत के हित पर एक टिप्पणी लिखिये। (200 शब्द) 12.5
For India BIMSTEC is important for both, 'Neighbourhood First' and 'Act East Policy'. Explain the statement and comment on the interests of India that would be served by regional cooperations. (200 words) 12.5

बिम्सटेक मे सात देश शामिल हैं- नेपाल, म्यांमार, भूटान, भारत, बांग्लादेश, थाईलैण्ड, श्रीलंका।

यह संगठन तकनीकी सहयोग, आर्थिक विकास व सामुद्रिक सुरक्षा पर आधारित है

यह संगठन भारत के नेबरहुड फर्स्ट के अनुरूप है क्योंकि इसमें भारत के अधिकांश पड़ोसी देश - नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका ~~शामि~~, बांग्लादेश। शामिल है।

भारत की इस नीति के अंतर्गत सहयोग, गैर-पारस्परिक → गुजराल सिद्धांत), संप्रभुता की रक्षा, एक दूसरे के हितों का सम्मान करने जैसे तत्वों को शामिल किया गया है, जिसका बिम्सटेक में पर्याप्त समावेशन किया है।

वहीं एक्ट ईस्ट नीति के दो प्रमुख देश म्यांमार व थाईलैंड

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

इसमें शामिल है भारत की एक्ट ईस्ट नीति विस्तारित पड़ोस की नीति है इस नीति के माध्यम से उत्तरपूर्वी भारत में स्थिरता, सुरक्षा, विकास को प्रोत्साहन दिया जा रहा है

इस संदर्भ में अनेक स्तरीय साझेदारी है –

→ कनेक्टिविटी के क्षेत्र में कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, त्रिपक्षीय राजमार्ग (म्यांमार – थाईलैंड – भारत), BBIN (भारत – बांग्लादेश – भूटान – नेपाल) जैसी योजना प्रमुख है

→ सैद्धांतिक रूप से इन देशों के मध्य 2005 में मुक्त व्यापार समझौता हस्ताक्षरित हो गया था परंतु अभी इसका क्रियान्वयन बाकी है

→ एक-दूसरे देशों में आसान वीजा प्रणाली, छात्रवृत्तियाँ प्रदान करना जैसी साझेदारी है

→ भारत – नेपाल, भारत – म्यांमार के मध्य सीमा पारगमन संधियाँ है

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

परंतु इस संगठन को प्रभावशाली बनाने के लिए जरूरी है - इसकी नियमित बैठकें हों, एक स्पष्ट अधिदेश हो, व्यापक कनेक्टिविटी हो, शरणार्थी समस्या (रोहिंग्या) का समाधान हो, अधूरे प्रोजेक्ट समय पर पूरे हों आदि।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि
The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

19. 'ईरान और सऊदी अरब के मध्य संघर्ष के वातावरण ने अक्सर पश्चिमी एशिया की राजनीति को अस्थिर किया है। फिर भी भारत ने हर संभव इन दोनों देशों के साथ बेहतर संबंध बनाए रखने का प्रयास किया है।' राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भारत के इस प्रयास के निहितार्थ दर्शाइये। (200 शब्द) 12.5

'The conflict of Iran and Saudi Arabia has often destabilized the politics of West Asia but India has tried to maintain a good relation with both these nations.' From strategic and economic perspective, discuss the significance of this effort of India. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

ईरान व सऊदी अरब में नेतृत्व, शिया-सुन्नी मुद्दे, सीरिया-इराक-यमन में ईरान की भूमिका को लेकर सऊदी अरब की नाराजगी आदि के कारण संघर्ष व तनावमय वातावरण बने है।

परंतु भारत ने पश्चिमी एशिया की इन दोनों क्षेत्रीय शक्तियों के साथ संतुलनकारी स्थिति को लुक वेस्ट नीति के अनुरूप स्वरूप प्रदान किया है।

भारत ने किसी भी शक्ति का क्षेत्रीय विवादों, धार्मिक विवादों व आपसी आरोप-प्रत्यारोपों से तटस्थ रहने की नीति अपनायी है।

भारत ने हालिया सऊदी अरब व ईरान की शीर्ष स्तरीय यात्रा व मेजबानी की है भारत चीन के प्रभाव को नियंत्रित

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

करने के लिए किसी एक पक्ष के समर्थन में जुड़ने से बचता है

इस नीति का लाभ यह रहा कि भारत ने दोनों देशों से ऊर्जा सुरक्षा हेतु पर्याप्त गैस व तेल आपूर्ति को बनाये रखा है भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 50% इन दोनों देशों से आयात करता है

वहीं डायस्पोरा की सुरक्षा के लिए भी भारत ने संतुलनकारी रवैया अपनाया है भारत के कुल विप्रेषण का लगभग 70% इसी क्षेत्र से आता है

चाबहार बंदरगाह के माध्यम से मध्य एशिया तक पहुँच के लिए भी भारत ने संतुलनकारी रवैया अपनाया है सऊदी अरब से भारत में पर्याप्त निवेश होता है अतः इसमें वृद्धि के लिए भी भारत ने यह नीति अपनायी है

इस नीति के माध्यम से भारत चीन को संतुलित करने में सफल रहा

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

है भारत को शीर्ष वैश्विक संस्था जैसे सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता, NSG में भागीदारी हेतु पर्याप्त समर्थन मिला है

आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता पर भारतीय पक्ष का इन देशों द्वारा समर्थन किया गया है

अतः हालिया संयुक्त राज्य अमेरिका व ईरान परमाणु समझौते से भारत रवैया में विचलन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है अतः भारत को दूरदर्शी रूप से निर्णय लेना चाहिए।

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

20. यह सर्वविदित है कि पूरे विश्व में भारतीय डायस्पोरा का न केवल प्रसार है बल्कि महत्त्व भी है। इस दृष्टिकोण से भारत को भारतीय डायस्पोरा के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण बनाए रखना उपयुक्त है। भारतीय डायस्पोरा का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए कथन की तर्कसहित पुष्टि कीजिये। (200 शब्द) 12.5

The Indian diaspora has not only expanse but also importance in the world. This drives India to have a favourable approach towards them. Explain the meaning of Indian diaspora and justify the given statement. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

डायस्पोरा से तात्पर्य है किसी देश के लोगों का स्थायी या अस्थायी रूप से सामाजिक-आर्थिक कारणों से गमन करना।

वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट के अनुसार समस्त विश्व में भारतीय डायस्पोरा की संख्या 17 मिलियन है जो विश्व में सर्वाधिक है। यह सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, सं०रा० अमेरीका, यूरोप, अफ्रीका में पर्याप्त रूप से विस्तरित है।

भारतीय डायस्पोरा का पर्याप्त महत्व है –

→ 2017 में भारत ने $69 billion का विप्रेषण प्राप्त किया जो विश्व में सर्वाधिक है

→ ये विदेशों में भारत की सॉफ्ट पावर के रूप में कार्य करते हैं।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

जैसा कि भारत - अमेरीका सिविल न्युक्लियर डील में भारतीय डायस्पोरा की महती भूमिका रही है

→ ये निवेश में महती भूमिका निभाते है जैसे ब्रिटेन से मित्तल उद्योग समूह।

→ ये संस्थागत व राजनीतिक संबंधों, सांस्कृतिक प्रचार में भी भूमिका निभाते है। जैसे पुर्तगाल व आयरलैंड के प्रधानमंत्री भारत मूल के है।

भारत डायस्पोरा के प्रति अनुकूल नजरिया अपनाये रखा है जैसे—

→ प्रवासी भारतीय मंत्रालय की स्थापना की गयी है

→ प्रवासी भारतीय दिवस (8 अगस्त) व प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन।

→ नौ इंडिया, स्टडी इन इंडिया जैसे कार्यक्रम चलाये है

→ भारतीय डायस्पोरा पर संकट आने पर भारत ने अग्रसक्रिय भूमिका निभायी

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

है जैसे यमन में ऑपरेशन संकटमोचन का संचालन।

→ शीर्ष भारतीय राजनीतिक नेतृत्व द्वारा विदेशों में सभाओं को संबोधित करना।

इस तरह स्पष्ट होता है कि न केवल विदेश संबंध बल्कि आर्थिक विकास हेतु डायस्पोरा का पर्याप्त योगदान है।

Feedback

Questions ....

Model Answer & Answer Structure ....

Evaluation ....

Staff ....

Copyright – Drishti The Vision Foundation

प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

इसमें बीस प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में छपे हैं।

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।

प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:

*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and in **ENGLISH**.*

All the questions are compulsory.

The number of marks carried by a question is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

समग्र मूल्यांकन
(Overall Evaluation)

Copyright – Drishti The Vision Foundation